



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र०० ग्रामियर केम्प, भोपाल

R1487-PB247 निगरानी क्रमांक - /2017

मायाराम आयु-लगभग 55 वर्ष  
पुत्र स्व० गिरधारीलाल निवासी ग्राम  
कानासैया, तह. हुजूर जिला भोपाल -----पुनरोक्षणकर्ता/आवेदक

### विलङ्घ

रामचरण आयु-62 वर्ष व नारायणसिंह  
आयु-50 वर्ष पुत्र सरदारसिंह निवासी-  
ग्राम कानासैया तह. हुजूर जिला भोपाल -----अनावेदक/प्रतिकारी

*(85)* अभियायक भी आरटीएन. माननीय  
द्वारा आयु दिनांक ०५/११/१८ परिवर्तित की गयी।

अभियायक दिनांक ०५/११/१८  
परिवर्तित की गयी।

२५/११

दि २३-८-१८७८  
माननीय ग्राम

२३-८

पुनरोक्षणकर्ता की और से माननीय अनुविभागीय अधिकारी तह. हुजूर जिला भोपाल द्वारा अपील प्र.क्र. 130/अपील/15-16 मायाराम वि० रामचरण व अन्य में धारा-5 अवधि विधान में पारित आदेश दिनांक 12-4-2017 से परिवेदित होकर निम्न वैधानिक अधिकारों तथों पर निम्नानुसार पुनरोक्षण प्रस्तुत है :-

1- यह कि माननीय अधिस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि और प्रक्रिया के विलङ्घ पारित होने से निरस्त होने योग्य है।

2- यह कि माननीय न्यायालय द्वारा रिकार्ड के विपरोत आदेश पारित कर वैधानिक भूमि की है के कारण भी पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

3- यह कि मान० अधिस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में दर्शितथों का विपरीत विवेचन कर आवेदन निरस्त कर और न्याय दृष्टिकोणों पर ध्यान न देकर अभियेक प्रस्तुत होने के बाद भी उसको पढ़ा नहीं गया और उसका विपरोत विवेचन कर पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

### प्रकरण के तथ्य

1- यह कि माननीय अधिस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने तहसीलदार तह. हुजूर जिला भोपाल द्वारा नामांतरण पं.क्र. 14 ग्राम कानासैया में पारित नामांतरण आदेश को प्रश्ननगत कर अपील पेश की थी और बताया गया था कि उक्त नामांतरण विधि विपरीत है कोई भी नामांतरण वकीयत नामे के साथी गण का परोक्षणकिये बिना वसोयत नामे को सिद्ध नहीं माना जा सकता,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1487-पीबीआर/2017 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एन0मालवीय एवं अनावेदक की ओर से श्री देवेन्द्र साहू अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(मनाज गोयल)</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> 	